पत्रिका

विकासोन्मुखी कदमों के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के समग्र विकास के लिए सरकार अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुकी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अपनी कोशिशों से हम रियासत में अमन और तरक्की की नई इबारत लिख पाएंगे

खुशहाली की ओर जम्मू-कश्मीर

रमेश पोखरियाल निशंक

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री

कश्मीर घाटी के प्रवास के बाद श्रीनगर से जहाज ज्यों ही घाटी के ऊपर आया मुझे ढाई वर्ष पूर्व की अपनी इंडोनेशिया यात्रा याद आ गई। सर्जनवीयता विश्वविद्यालय योग्यकार्ता इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति पर मेरे व्याख्यान के पश्चात एक छात्रा ने पूछा था कि आपसी वैमनस्य, आतंक से ग्रस्त नित-प्रतिदिन बदलते वैश्विक परिवेश में दुनिया की दूसरी बड़ी मुस्लिम आबादी और अन्य धर्मों की विविधता के साथ भारत के लोग आपस में कैसे सामंजस्य बैठा पाते हैं? मैंने बड़ी सहजता से उत्तर दिया था कि इसके लिए हमें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। युग-युगांतर से चली आ रही हमारी अजर, अमर भारतीय संस्कृति हमें एकता, समरसता, सहयोग, भाईचारा, सत्य, अहिंसा, त्याग, विनम्रता, समानता आदि जैसे मूल्यों में आबद्ध कर हमें 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।

मैंने उन्हें बताया की किस प्रकार सवा सौ करोड़ की जनसंख्या के साथ भारत एक देश नहीं बल्कि पूरा उपमहाद्वीप है, जिसके विभिन्न भागों में अलग-अलग रीति रिवाज और अलग-अलग परंपराएं हैं। विविधता के जितने दर्शन भारत में होते हैं उतना शायद ही विश्व के किसी अन्य क्षेत्र में होते होंगे। आज जब मैं दो दिन के प्रवास के बाद कश्मीर से लौटा हूं तो मेरी यह धारणा और मजबूत हुई है। मैं पूरी शिद्दत से यह महसूस करता हूं कि मेरी धारणा बिलकुल सही थी। कश्मीर के विद्यार्थियों, अध्यापकों, प्रतिनिधिमंडलों, जनसामान्य से मिलकर एक बात साफ हुई कि घाटी में सब अमन चैन चाहते हैं। सब अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं। संगीनों के साए में भय के वातावरण में कोई नहीं रहना चाहता। लोग खुशहाल भविष्य, खुशहाल कश्मीर चाहते हैं।

> भारत एक देश नहीं बल्कि पूरा उपमहाद्वीप है, जिसके विभिन्न भागों में अलग-अलग रीति रिवाज और अलग-अलग परंपराएं हैं। विविधता के जितने दर्शन भारत में होते हैं उतना शायद ही विश्व के किसी अन्य क्षेत्र में होते होंगे।

कश्मीर की सहिष्णुता और बहुलतावादी सोच से साक्षात्कार श्रीनगर में हो जाता है जब एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में सैकड़ों वर्ष पुराने डल झील के समीप समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव को समर्पित प्राचीन शंकराचार्य मंदिर के दर्शन होते हैं। प्रधानमन्त्री मोदी की विकासात्मक दूरदृष्टि में कश्मीर के उज्ज्वल भविष्य का प्रतिबिम्ब दिखता है। सरकार ने समग्र विकास की बात की है ताकि जम्मू कश्मीर में रहने वाले डोगरा, कश्मीरी पंडित, लद्दाख के लोग, सिख और ईसाइयों के साथ ही सुन्नी, शिया, गुज्जर,

कश्मीर की सहिष्णुता और बहुलतावादी सोच से साक्षात्कार श्रीनगर में हो जाता है जब एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में सैकड़ों वर्ष पुराने डल झील के समीप प्राचीन शंकराचार्य मंदिर के दर्शन होते हैं। उसी डल झील का शुक्रवार को लिया गया खूबसूरत चित्र।

बक्करवाल और पहाड़ी जैसे विभिन्न कश्मीरी मुस्लिम समुदायों के रूप में मौजूद कश्मीरी जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप जम्मू कश्मीर का निर्माण हो सके।

मेरा मानना रहा है कि जम्मू-कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 के माध्यम से विशेष दर्जा देने के कारण ही जम्मू-कश्मीर विकास की मुख्य धारा से वंचित रह गया। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 'एक विधान, एक प्रधान, एक निशान' की नीति को पूर्ण रूप देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को ऐतिहासिक फैसला करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35-ए को निष्प्रभावी करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का फैसला लिया जिसके तहत 31 अक्टूबर, 2019 से राज्य की जगह दो केंद्रशासित प्रदेशों की व्यवस्था अस्तित्व में आ गई। अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर को नाममात्र की स्वायत्तता हासिल थी लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया ताकि इलाके में विकास को बढ़ावा देने के साथ आतंकी गतिविधियों को रोका जा सके।

संसद से पारित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के तहत जम्मू-कश्मीर विधानसभा के साथ केंद्रशासित प्रदेश बन गया और दूसरी ओर लद्दाख बिना विधानसभा वाला सीधे केंद्रशासित बन गया है। दरअसल मौजूदा केंद्र सरकार को यह लगा कि बीते सात दशकों से कश्मीर में कहीं भी विकास नहीं हो पाया।

सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा है कि स्वयं हमारे देश में खुद को 'अभिजात्य' समझने वाला वर्ग सब को यह डराते हुए उद्घोषणा करता था कि भारत में 370 या 35ए को हटा पाना असंभव है। और, यह भी कहा जाता था कि अगर यह कदम उठाया गया तो देश के एकता अखंडता खतरे में पड़ जाएगी परन्तु प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह संपूर्ण देश को एकत्रित कर इस अनुच्छेद को निरस्त करने का महत्वपूर्ण कार्य किया उसने पूरे विश्व में भारत की कीर्ति पताका को ऊंचा किया है। आज कश्मीर में शांति और सद्भावना का एक ऐसा वातावरण सृजित करने का ईमानदार प्रयास है जिससे नए जम्मू-कश्मीर के निर्माण की परिकल्पना को साकार किया जा सके। पिछले हफ्ते मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालयों के 45 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, जिसमें स्कूलों के दो दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण निष्ठा कार्यक्रम के अलावा शैक्षिक उत्थान के कई अन्य प्रोजेक्ट शामिल हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू के श्रीनगर परिसर का उद्घाटन किया गया और 15 मार्च 2020 तक इस अस्थाई परिसर को पूरी तरह से चालू करने के लिए 51 करोड़ रुपए मंजूर किए गए।

प्रधानमंत्रीजी की अगुवाई में पूरी सरकार जम्मू और कश्मीर में शांति, खुशहाली और विकास की ओर अग्रसर है। बजट 2020 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए उदार हृदय से आवंटन किया है। क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जम्मू-कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपए और लद्दाख के लिए 5,958 रुपए का ऐलान किया है। सरकार अपनी पूरी सामर्थ्य से कश्मीर के विकास के लिए कार्य कर रही है। यह हमारा सौभाग्य है कि मजबूत नेतृत्व के चलते विश्व परिदृश्य में भारत को सम्मान से देखा जाता है। ऐसे में पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने पर अलग-अलग देशों के साथ मिलकर इसे वैश्विक मंच पर उठाने की पुरजोर कोशिश की। लेकिन जवाब में उसकी फजीहत ही हुई।

प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर के समग्र विकास के लिए आत्मनिर्भरता, विकास, औद्योगिक क्रांति, रोजगार सृजन और खुशहाली का विशिष्ट दृष्टिकोण है। जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से केंद्रीय अनुदान पर निर्भर करती है। उद्योग व वाणिज्य संघ के अध्यक्ष शेख आशिक के अनुसार, 'अगर हम राज्य में बेरोजगारी की समस्या दूर कर सकें तो कश्मीर की 95 फीसदी समस्या दूर हो जाएगी।' हमारी सरकार का लक्ष्य है कि सर्वप्रथम राज्य की अर्थव्यवस्था जो खेती और सेवाओं पर निर्भर है उसे मजबूत किया जाए। राज्य के पर्यटन, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन, हैंडलूम, बागवानी, फूड प्रोसेसिंग और कृषि को विकसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि राज्य में औसत बेरोजगारी दर जो 15 फीसदी रही है, को कम किया जाए। मैं मानता हूं कि इस राज्य में प्रगति के युग का सूत्रपात कर ही हम क्षेत्र में शांति, समृद्धि, समरसता, प्रेम, भाईचारे और खुशहाली का वातावरण सृजित कर सकते हैं। विकासोन्मुखी कदमों के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के समग्र विकास की लिए सरकार अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुकी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अपनी कोशिशों से हम रियासत में अमन और तरक्की की नई इबारत लिख पाएंगे।